revenue. We have the mining industry in Goa by which, I think, we are having ample revenue, and most of the revenue cannot be collected in the absense of a full-fledged Income Tax Commissionerate in Goa. Therefore, I would request the hon. Finance Minister to see that a full-fledged Commissionerate of Income Tax is opened in Goa. Of course, he will have the problem of creation of a post. In the absence of that, I would request him to transfer a post of Commissioner of Income Tax lying vacant elsewhere in the country to Goa. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BIPLAB DASGUPTA): Shri Naresh Yadav

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Sir, my name is there.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BIPLAB DASGUPTA): Yours is next. Please sit down.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: I should be called, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BIPLAB DASGUPTA): Allow Mr. Yadav to speak, please.

SERIOUS PROBLEMS ARISING OUT OF EROSION BY THE RIVER GANGA IN BIHAR

श्री नरेश यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार में 14 जिलों में बाढ़ की विभीषिका की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिहार में बक्सर से ले कर शाहबगंज तक 438 किलोमीटर गंगा नदी बहती है। बिहार में गंगा नदी के तेज कटाव से आज 14 जिले प्रभावित हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर उ०प्र० के कुछ इलाके को छोड़ दिया जाए तो दोनों आर-पार में कुल 600 किलोमीटर आज गंगा नदी से प्रभावित है। मैं इस गंभीरता की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। प्राकृतिक आपदा कोष बिहार को मात्र 49.4 करोड़ रुपये दिया गया है जो बहुत कम है। इसे बढ़ाया जाना चाहिये। बिहार के 14 जिलों में 76 प्रतिशत आबादी पूर्णतया बाढ़ से प्रभावित है। यहां तक कि आज बिहार के किसानों की सम्पूर्ण जान माल की क्षति हो रही है। हजारों एकड़ जमीन बरबाद हो गयी है। इसलिए श्रीमन, मैं इस सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि 1 अरब 30 करोड़ रुपए की जो मांग बिहार सरकार ने की है वह रुपया उसे मिलना चाहिए बिहार की बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए। अंत में, मैं श्रीमन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि ऐसे गंभीर मामलों पर जिससे बिहार बरबाद और तबाह है तुरंत ध्यान देना चाहिए और जल संसाधन मंत्री को एक केन्द्रीय दल वहां की बाढ़ की विभीषिका को देखने के लिए भेजना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री एस०एस० अहलुवालिया (बिहार): महोदय मैं नरेश यादव जी के इस विशेष उल्लेख का समर्थन करते हुए यह मांग करना चाहता हूं कि दियारा इलाके के लोग एक तो जब सुखा पड़ जाता है तो पानी नीचे उतर जाने के कारण भी भोगते हैं। दूसरे कोई भी सरकारी डेवलपमेंट का काम वहां इसलिए नहीं होता है कि लोग कहते हैं कि जब बारिश होगी बाढ़ आएगी तो यह डूब जाएगा। उस वक्त भी उनको न्याय नहीं मिलता है क्योंकि कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। जिस वक्त बाढ़ आती है तब भी उन्हें कोई देखने नहीं जाता है। इस कटाव में बड़े से बड़े गांव, खेत, उपजाऊ खेत सब डूब जाते हैं। बहुत नुकसान होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इस कटाव को आइंदा आने से किस तरह से रोका जा सकता है और गंगा के उस एरिया में डीसिल्टेशन का क्या प्रोग्राम लिया जा सकता है इसके लिए वाटर रिसोर्स मिनिस्टर की एक हाई पावर टीम वहां भेजनी चाहिए। ड्रेजिंग कारपोरेशन को वह काम सौंपना चाहिए कि ड्रेजिंग करके उसका बेड और डीप बनाया जाए जिससे कि गंगा वहां न फैले और उसके कटाव में हमारे खेत, खलिहान और गांव न डूबें। उसका उपाय ढूंढने की जरूरत है।

UNPRECEDENTED FLOOD SITUATION IN BIHAR

श्री रजनी रंजन साहू (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे विशेष उल्लेख का विषय बाढ़ से पीड़ित उन लोगों के संबंध में है जो अकारण प्रकृति के प्रकोप से पीड़ित हैं। उत्तर बिहार के 50 लाख से अधिक लोग 12 जिलों में फैले...

श्री नरेश यादव: अब 14 जिले हो गए हैं।

श्री रजनी रंजन साहू: 14 जिले समझ लीजिए। इनमें 40 प्रखंड इस बाढ़ से प्रभावित हैं, वहां बाढ़ से जलमग्न हैं और विभिन्न तटबंधों पर तेज कटाव जारी है। सीतामढ़ी जिले के बाढ़ में डूबकर मरने वालों की संख्या

आज की तारीख में सरकारी सूत्रों के अनुसार 23 हो चुकी है और सरकारी सूत्रों के मुताबिक जो इसमें प्रभावित लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा गरीब हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। कमला बालान नदी का जल स्तर पिछले दिनों खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। दरभंगा से प्राप्त सूचना के अनुसार कमतौल के अधवारा समूह के जल स्तर में पिछले 24 घंटों में 17 सेंटीमीटर की बढ़ोत्तरी का अनुमान है। अधवारा समूह नदी में बाढ़ का पानी निकटवर्ती सभी प्रखंडों में फैल गया है। यद्यपि राज्य सरकार ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के बचाव एवं राहत कार्यों के लिए 81 सरकारी एवं निजी नावों को तैनात किया है पर राज्य सरकार, अपने सीमित साधनों से, वह नहीं कर पा रही है।

मैं बताना चाहूंगा सदन को कि अभी तक यह सब जो बाढ़ आई है यह तटबंधों के रखरखाव न होने की वजह से आई है। सरकारी समायोजन में 35 हजार रुपए प्रति किलोमीटर की दर से तटबंधों को सुरक्षित किए जाने में खर्च करने का अनुमान रखा गया है पर पिछले पांच सालों में 400 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से रखरखाव पर खर्च हुआ है। इसके अलावा और भी जो रुपया चाहिए वह रिलीज नहीं हो पाया है। इन तटबंधों की सुरक्षा और जो अभी बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता और बाढ़ समाप्त होने के बाद जो बीमारी फैलेगी इन सबके लिए जो आवश्यकता है मैं उसकी तरफ केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और हमारे बिहार के डा० जगन्नाथ मिश्र जी केन्द्रीय सरकार में मंत्री हैं, वे इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां... एक टीम वाटर रिसोर्सेज.... (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: जगन्नाथ जी राष्ट्र के हैं.... (व्यवधान)

श्री रजनी रंजन साहू: नहीं, वह बिहार से आते हैं, लेकिन भारत सरकार के मंत्री हैं। अब इनका दायित्व ज्यादा है। जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हैं, हैल्थ मिनिस्टर हैं और वित्त मंत्रालय है, ये सारे लोगों की एक टीम बनाकर मैं मांग करता हूं इस सदन के माध्यम से कि डा० मिश्र जी के नेतृत्व में यह चारों विभाग से भारत सरकार की टीम तत्काल वहां जानी चाहिए ताकि लोगों में जो बीमारी फैलने वाली है, लोग अभी जो तबाह हैं, उनके लिए राहत और दवा इत्यादि की व्यवस्था की जा सके।

श्री रामदेव मंडारी (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, बिहार में हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ आने के कारण हैं कि वे नदियां नेपाल से चलती हैं, कमला बलान, कोसी जैसी नदियां नेपाल से चलती हैं और नेपाल में जब पानी ज्यादा हो जाता है तो वह पानी छोड़ देते हैं और एकाएक उत्तरी बिहार में बाढ़ आ जाती है। महोदय, डा० जगन्नाथ मिश्र जी, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं झंझारपुर क्षेत्र, 22 वर्ष एम०एल०ए० रहे हैं और तीन बार वह बिहार के मुख्य मंत्री रहे हैं, और माननीय चतुरानन मिश्र जी भी मधुबनी जिला से आते हैं। मैं भुक्तभोगी हूं इस बाढ़ का। जिस दिन झंझारपुर में कमला बलान नदी का बांध टूटा उस दिन मैं झंझारपुर में था, बाद में वहां डा० साहब भी गए थे जैसे ही उन्हें जानकारी मिली। हर साल वहां बाढ़ आती है कोसी में, कमला में, मगर इस बार की बाढ़ कुछ भयानक स्थिति में आ गई है। इस बार की बाढ़ ने कमला बलान तटबंध की 6 जगह तोड़ा है, और आप इसी बात से बिहार में नुकसान का अनुमान लगा सकते हैं कि 25 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। 14 जिला, 75 प्रखंड, लगभग 700 पंचायत, 2 हजार गांव, 9 हजार मकान, 4 लाख हेक्टेयर भूमि में लगी फसल और 23 जानें इस बाढ़ में गई हैं। बिहार सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है। मुख्य मंत्री जी ने भी कई बार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। पूरी व्यवस्था हो रही है। मगर महोदय, जो एक प्राकृतिक विपदा है उसका कोई भी राज्य सरकार अकेले मुकाबला नहीं कर सकती है। इतने बड़े पैमाने पर जो प्राकृतिक विपदा आई है कोई भी राज्य सरकार उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। केन्द्रीय सरकार जब तक अपनी ओर से राज्य सरकारों को ऐसी विपदाओं में मदद नहीं करेगी तब तक राज्य सरकार उसका पूरी तरह मुकाबला नहीं कर पाएगी। 100 करोड़ से ज्यादा रुपये का, अभी मेरे भाई श्री दिनेश यादवजी कह रहे थे कि 138 करोड़ रुपये का डिमांड बिहार सरकार की ओर से आया है। डाक्टर साहब का बयान अखबार में छपा था। मैंने पढ़ा था कि डाक्टर साहब श्री विद्याचरण शुक्ल जी से बात करेंगे, उन नदियों के तटबंध को किस तरह से बचा कर रखा जाए। तो डाक्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अच्छी तरह जांच लें। 22 साल तक एम०एल०ए० रहे हैं बिहार के तीन बार मुख्य मंत्री रहे हैं, बिहार की समस्याओं के बारे में खास कर बाढ़ की समस्या के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री रजनी रंजन साहू: अभी केन्द्र के मंत्री हैं

...(**व्यवधान**)... गए थे। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदेव भंडारी: वे, गए भी थे। मैंने कहा है मैं आभारी हूं, मैं धन्यवाद देता हूं डाक्टर मिश्रजी को और मैं चाहता हूं कि डाक्टर साहब केन्द्रीय सरकार की ओर से, बिहार का जो 138 करोड़ रुपये का डिमांड आया है बाढ़ सहायता के लिए, क्योंकि वहां पर रेल का लाइन टूट गया है, बांध टूट गया है, सड़कें खत्म हो गई हैं, मैं अपने घर पर नाव से ही जा पाऊंगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है मुझे घर पर जाने के लिए, नाव से नदी पार करनी पड़ेगी तब मैं अपने घर जा पाऊंगा, ऐसी स्थिति में मैं डाक्टर साहब से अनुरोध करुंगा कि केन्द्रीय सरकार से बिहार को कम से कम 150 करोड़ रुपये दिलवायें जिससे कि बिहार की जो बाढ़ से उत्पन्न समस्यायें हैं उनको दुरुस्त किया जा सके।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

[**Vice Chairman (SHRI MD. SALIM)** in the Chair]

श्री रजनी रंजन साहू: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय केन्द्रीय मंत्री जी का ध्यान चाहूंगा कि यह आज हमें आश्वासन दें। वह बिहार से आते हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): देखिए, हालात को ऐसा मत बनाइए कि लोग समझें कि बिहार के बारे में चर्चा हो रही है।

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं को इस से सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि अभी बिहार में बाढ़ की विभीषिका है, खासकर उत्तर बिहार के 14 जिलों में भारी बर्बादी हुई है। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दक्षिण बिहार और मध्य बिहार में पानी न पड़ने के कारण सूखा भी पड़ चुका है। मैं डा० मिश्र जी से कहना चाहूंगा कि उत्तर बिहार बाढ़ से और मध्य और दक्षिण बिहार सूखे की चपेट में है, इसलिए केन्द्र सरकार एक टीम भेजे जो कि स्थिति की समीक्षा कर कटाव पीड़ित और बाढ़ पीड़ितों को सारी सहायता उपलब्ध कराए और उन का बचाव करते हुए वहां जो खतरा सुखे से उत्पन्न होने वाला है, उस की भी समीक्षा करें और बाढ़ और सूखे से बिहार की जनता की रक्षा करें।

महोदय, बिहार की सरकार इस स्थिति में नहीं है कि इस स्थिति का आर्थिक तौर पर मुकाबला कर सके, इसलिए बिहार सरकार को केन्द्र सरकार की ओर से डेढ़ अरब क्या, जरुरत पड़े तो दो अरब भी दिए जाएं और मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय टीम के साथ डा० जगन्नाथ मिश्र जी खुद जाएं और दोनों स्थितियों का जायजा लेकर बिहार की जनता को इस मुसीबत से राहत प्रदान करें, उनकी रक्षा करें। धन्यवाद।

श्री महेश्वर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने को इस के साथ सम्बद्ध कर रहा हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): You cannot associate.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: The Minister should react.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): If he wants to react, he cant do so. But I cannot ask the Minister to react.

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): नरेश यादव जी, आप भी बैठ जाइए। बिहार के बारे में आपने इतने सवाल उठाए हैं, अब मंत्री जी को सुन लीजिए।

ग्रामीण विकास मंत्री (डा० जगन्नाथ मिश्र): उपाध्यक्ष महोदय, जहां ऐसी गंभीर स्थिति बनती है, केन्द्र सरकार की ओर से टीम भेजी जाती है। बिहार की बाढ़ की समस्या की जानकरी है और कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय व जल-संसाधन मंत्रालय की ओर से तत्काल ही टीम भेजी जाएगी जब राज्य सरकार की ओर से पर्याप्त ज्ञापन प्राप्त हो जाएगा।

श्री नरेश यादव: ज्ञापन प्राप्त हो चुका है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): अभी स्पेशल मेंशंस में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन वोरा कमेटी की रिपोर्ट पर जो चर्चा चल रही थी, उस का चार घंटे का समय तो खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ पार्टीज के मेंबर्स बच गए हैं।

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता: महोदय, स्पेशल मेंशंस हो जाने दीजिए क्योंकि ये दो दिन से टल रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): टलेगा नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। अभी ढाई बजे से हम वोरा कमेटी की रिपोर्ट पर अधूरी चर्चा शुरु करने वाले थे। एक घंटे में उस चर्चा को समाप्त कर देंगे फिर पेंडिंग स्पेशल मेंशंस लिए जाएंगे।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं आप के सुझाव का समर्थन करता हूं क्योंकि इस के दो

लाभ होंगे-एक तो स्पेशल मेंशंस वाले इस बहाने हाउस में बैठेंगे और दूसरे उपस्थिति बनी रहेगी।

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्पेशल मेंशंन दिया था जोकि 6 दिन से पोस्टपोन रेगुलरली हो रहा है। मेरे स्पेशनल मेंशन का सब्जैक्ट बहुत इम्पोर्टेन्ट है कि इंडियन रेडक्रास ने एच०आई०वी० पोजिटिव ब्लड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट किया है। दो साल से यह चलता आ रहा है। इस विषय को मैं उठाना चाह रहा हूं, लेकिन 6 दिन से यह पोस्टपोन हो रहा है।

SHRI PARAG CHALIHA: I have been waiting for thirteen days for my Special Mention.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): The problem is, we have to finish it. Only two or three days left. Special Mentions and Zero Hour submission were pending for several days. that is why there are so many names in the list. We will try to finish these after the debate on Vohra Committee's Report. Already several speakers have made their Zero Hour submissions and on Special Mentions also they were asked to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): But we cannot finish it immediately. there are several names. So, let us take up the further discussion on the Vohra Committee Report. Then, immediately after that, we will take up the rest of the special mentions. If you all cooperate, we will do like that.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

प्रो० राम बख्श सिंह वर्मा: मान्यवर, पहले स्पेशल मेंशन ले लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Okay. Mr. Satya Prakash Malaviya. ...*(Interruptions)*... Please sit down.

AN HON. MEMBER: Is the Home Minister coming?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Sayeed is here. The Home Minister will also be coming.

Yes, Mr. Malaviya. You have to restrict it to five minutes.

प्रो० राम बख्श सिंह वर्मा: मैं इसके विरोध में हाऊस से वाक-आऊट करना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): I may be given time according to the time given to the other parties.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Yes.

SHORT-DURATION DISCUSSIN ON NEXUS BETWEEN POLITICIANS AND CRIMINALS IN THE CONTEXT OF VOHRA COMMITTEE REPORT-CONTD.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हम यहां पर एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्र का जो एग्जिसटेंस है वह भी संबंधित है। अपराधियों, माफिया संगठनों, सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों और राजनैतिक नेताओं के साथ सांठगांठ की जानकारी करने के लिए बोहरा कमेटी की नियुक्ति 9 जुलाई, 1993 को की गई थी। इसमें वोहरा साहब के अलावा चार और उच्चाधिकारी थे। उन्होंने 5 अक्तूबर, 1993 को सरकार को अपनी रिपोर्ट दी। पौने दो साल हो गया रिपोर्ट को दिए हुए। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट में इस बात की भी चर्चा है कि बंबई में पुलिस और बंबई के अपराध जगत के सांठगांठ के बारे में सी०बी०आई० ने कोई रिपोर्ट 1986 में तैयार की थी। तो वोहरा कमेटी की रिपोर्ट, जो पौने दो साल पहले आई थी और सी०बी०आई० की रिपोर्ट, जो 1986 में आई थी, उन पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। जो बहुत बड़े, उच्चाधिकारी थे सेक्रेटरी रेवेन्यू डायरेक्टर सी०बी०आई०, डायरेक्टर आफ इंटेलीजेन्स ब्यूरो और मैम्बर सेक्रेटरी, ज्वायंट सेक्रेटरी मिनिस्टरी आफ होम अफेयर्स, उन लोगों के मन में यह शंका थी कि सरकार कोई कार्यवाही करेगी या नहीं करेगी और यह अधिकारी स्वयं डरे हुए थे। इसकी चर्चा इसी रिपोर्ट में है-"विचार विमर्श के बाद मैंने यह देखा कि कुछ सदस्य खुलकर अपने विचार व्यक्त करने में हिचकिचा रहे थे और इस बात के प्रति